गया है, वह तो सैमी गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन है। वहां गवर्नमेंट की नीति यह तय करती है कि आप 6 महीने यहां काम करेंगे और 6 महीने आराम करेंगे या छुट्टी लेंगे। Each and every entrepreneur is a private entrepreneur. That is why they have to take that decision. The real problem is the non-availability of the trained staff. Here, we have taken two steps. Firstly, from 25 per cent, we have brought it down to 15 per cent. If there is a demand that we should give a second thought to it, I have said that I am ready to take some decision in this area. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या आप ट्रेनिंग के लिए institutes बनाएंगे?

SHRI SHARAD PAWAR: There are institutes. We have provided training facilities in these institutes, which are in Mumbai, Cochin, Chennai, etc. The only thing is that sufficient number of youngsters are not going to these institutes. So, we have to introduce some scholarships and a number of other things so that the local youngsters go there, get trained and fulfil the requirements of this country.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Revival of MFL

*182. SHRI TAPAN KUMAR SEN:††
SHRI MOHAMMED AMIN:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Madras Fertilizers Limited (MFL) has been referred to BIFR and if so, the reasons therefor;

(b) whether, as per the recommendation of BRPSE, if financial restructuring proposal to make the operation of the company viable has been finalized; and

(c) if so, the details thereof and other steps being taken to revive MFL?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A Satement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. Madras Fertilizers Limited (MFL) produces Ammonia, Urea and Complex fertilizers (NPK) based on Naphtha as feedstock. The cost of production of urea in respect of MFL is highest in the country. Though the price concession rates enjoyed by the MFL is highest, it is not able to cover the actual cost of production and hence, the company continues to incur losses. Without the availability of gas, operations of MFL cannot be viable. Due to the continued losses, the net worth of the company has completely eroded. A reference was made to BIFR as a statutory requirement by the company and pursuant to this, it has been registered as a sick company by the BIFR.

Based on the recommendations made by the BRPSE and expected availability of gas by 2010-11, a financial restructuring proposal to make the operation of the company viable is under the active consideration of the Government.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, in the reply, it was mentioned that in spite of the price concession enjoyed by the MFL, it is not able to cover the actual cost of production. Sir, about a year ago, in reply to Unstarred Question No. 1828 in this House on 8.12.2006, it was stated that the BRPSE had made certain recommendations for financial restructuring of the Madras Fertilizers Limited, including some changes in pricing policies of fertilizers produced by it, under certain peculiar circumstances. Thirdly, the Tariff Commission has also recommended changes in the pricing formula in view of the peculiar, unique, production pattern of the Madras Fertilizers Limited. And, BRPSE in specific terms recommended a change in the pricing policy as one of the essential ingredients of its revival process, not merely infusion of capital. The change in the pricing policy is technically required-in view of the fact that the weighted average of the variable cost of the group fertilizers on the basis of which pricing is developed does not reckon the energy norms specified for MFL. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am coming to the question. Why I am saying this is because this is the basis of my question. The depreciation and capital cost related charges do not reckon the MFL's investment of Rs. 700 crores during 1993 and 1998. And, on this basis, the BRPSE recommended a change in the pricing scheme and enhancement of the RPS benefit. Sir, this is one of the most important and essential ingredients of the revival process, besides the infusion of capital fund. In December, 2006, it was said that that is under consideration. But till today, it has been pending.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So, will the hon. Minister kindly assure a time-frame — because he is quite interested in improving and revamping the public sector undertakings; he is committed to that — for reviving this important fertilizer plant and will he also consider the pricing formula which is a necessary ingredient?

श्री राम विलास पासवान: सर, MFL एक बहुत ही पुरानी और रेपुटेड कम्पनी है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई है कि पहले रिटैन्शन प्राइस होती थी कि जितना यूरिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था, उस कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर उनको प्राइस सब्सिडी दी जाती थी। बाद में उस कमेटी की रेकमेंडेशन के आधार पर न्यू प्राइस पॉलिसी लागू हो गई और जैसा कि आपने अपने आउट लेयर सिद्धांत के बारे में बतलाया है, उसमें 6 ग्रुप्स बनाए गए और उन 6 ग्रुप्स में नाफथा बेस्ड और गैस बेस्ड before 1992, after 1992 तय करके उसमें एवरेज निकाली गई। उसमें यह कहा गया कि उसके अलावा जिनको 20 परसेंट से ज्यादा घाटा होगा, उसमें सरकार उनको 50 परसेंट सब्सिडी देगी और 50 परसेंट उनको सहना पड़ेगा। इसके कारण इसका काफी घाटा हुआ है। पिछले तीन साल में 354 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसमें दो बार रिवाइवल पैकेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी हालत नहीं सुधर पाई है। इसकी हालत तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक गैस नहीं आ जाती है। आपका कहना ठीक है कि बी.आर.पी.एस.ई. में गया है। आप जानते हैं कि बी.आर.पी.एस.ई. के बाद गवर्नमेंट का एक प्रोसिजर होता है। इस प्रोसिजर के तहत बी.आर.पी.एस.ई. में गया, बी.आर.पी.एस.ई. में 1.12.2006 को उन्होंने अपनी

अनुशंसा दे दी, अनुशंसा के बाद उसे लेकर सी.ओ.एस. (कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज) में गए, सी.ओ.एस. ने 22.3.2007 को अपनी रिकमेंडेशन दी है और अब उसे कैबिनेट में ले जा रहे हैं। आपका जो आकलन है, वह बिल्कुल सही है। हम उससे टोटली सहमत हैं। चूंकि कैबिनेट में गया हुआ है, इसलिए हम डिटेल में नहीं बताएंगे कि हम कैबिनेट में क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने बता दिया था तो प्रिविलेज मोशन आ गया था।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my second supplementary question...

MR. CHAIRMAN: Please make it a sharply focussed question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes, Sir. I shall only put the question. I won't be saying anything else.

Sir, in the reply the hon. Minister has made a very clear statement that, without availability of gas, operations of MFL cannot be viable. In view of that, I would like to know whether the hon. Minister — and whether he also as a member of the empowered Group of Ministers for deciding the gas price — would kindly assure that pricing of gas that is about to be done in the EGOM would take care of the essential requirements so that the fertilizer sector, like the power sector, also gets a special and priority treatment in respect of pricing of gas and also in respect of allocation, In that process, I also feel that the gas pricing policy should not be such as to ensure windfall gain for some of the private contractors linked with the international crude price.

श्री राम विलास पासवान: सर, अभी हमारे पास जो प्लांट्स हैं, उसमें से करीब 70% प्लांट्स गैस बेस्ड हैं, 35% प्लांट्स नाफ्था बेस्ड और फ्यूल वॉयल बेस्ड हैं। जो 70% गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, उसमें हमें केवल 30% सब्सिडी देनी पड़ती है। हमारे पास जो 30% नाफ्था बेस्ड हैं, फ्यूल बेस्ड हैं, उसमें हमें 70% सब्सिडी देनी पड़ती है। इसके अलावा हमने अभी निर्णय लिया है कि हमारे जो एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. के बंद प्लांट्स हैं, जिसमें सात-आठ प्लांट्स हैं, इनमें गोरखपुर, बरौनी, हल्दिया, दुर्गापुर, रामागुंडम, सिंदरी प्लांट्स हैं, पिछली सरकार ने जो नाफ्था बेस्ड थे, उन्हें बंद कर दिया था, हमने उन्हें फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी गैस की आवश्यकता होगी। अभी हमें जितनी गैस चाहिए, उसमें काफी कमी है। 41 एमएमएस सीएमटी चाहिए, जिसमें 29 हैं...**(व्यवधान)**...इसमें हमने बारह के लिए कहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें निश्चित रूप से फर्टिलाइजर इसकी रीढ़ है, इसलिए फर्टिलाइजर को प्राथमिकता देनी चाहिए। कम से कम कीमत पर गैस उपलब्ध हो, इसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे।

श्री मोहम्मद अमीन: शुक्रिया। सर, पिछले जमाने में आदमी बीमार हुआ करते थे, अब कारखाने बीमार होने लगे हैं, कंपनियां बीमार होने लगी हैं। इनका इलाज दरयाफ्त करना भी बड़ा टेढ़ा है। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि वह गैस बेस्ड है और जब तक गैस नहीं आ जाती, तब तक इसके लिए कुछ करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि गैस मिलते-मिलते 2010-2011 तक हो जाएगा। तब तक तो इस कंपनी की गैस निकल जाएगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गैस बेस्ड और भी प्लांट्स हैं, जो सेहतमंद हैं, उनके साथ इसे मर्ज कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द यह कारखाना खड़ा हो सके।

श्री राम विलास पासवान: सर, असल मे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो बन्द कम्पनी है, उसको चालू करने के लिए हम लोगों ने पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लगाया है। अब पब्लिक अंडरटेकिंग्स में बरौनी को एनएफएल को दे दिया गया है, एनएफएल तैयार हो गया है, दुर्गापुर को आरसीएफ को दे दिया गया है, गोरखपुर को कृभको को दिया गया है, तलचर को आरसीएफ को दिया गया है, एनएफएल रामागुंडम को दिया गया है। लेकिन सिन्दरी, कोरबा, हल्दिया के लिए कोई नहीं आ रहा है। कोई भी प्राइवेट कम्पनी जब joint venture करेगी, तो वह घाटे का सौदा क्यों उठाएगी। जब हम जानते हैं कि यह नाफ्था बेस्ड प्लांट है और नाफ्था की cost of production high है, एमएफएल की सबसे ज्यादा है। इसकी cost 16 हजार पड़ जाती है और इसकी price 12 हजार है, तो इसका 4 हजार प्रति टन का घाटा है। सरकार की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के मुताबिक 50 परसेंट यानी 2 हजार इनको मिलता था यानी 2 हजार प्रति टन का घाटा है। वह घाटे का सौदा कोई नहीं खरीदना चाहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस कम्पनी को revive करें और इसके लिए हम लोग कैबिनेट में जा रहे हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please let the Member proceed.

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद सभापति महोदय। हमारा एनडीए है और सरकार यूपीए की है, लेकिन ...**(व्यवधान)**... सर, मैं प्रश्न के ऊपर आता हूँ, लेकिन सरकार में पासवान जी, अन्बूमणि रामदास जी जैसे कई व्यक्तित्व हैं, जिनके साथ ज्यादा तर्क-वितर्क करने के लिए मन मना करता है। वास्तव में वे काबिल मंत्री हैं और वे ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए न।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा यह निवेदन है कि जो उर्वरक कारखानें बन्द पड़े हुए हैं, अभी माननीय मंत्री महोदय उनकी सूची पढ़ रहे थे, मैं उस समय धीरज से सुन रहा था कि शायद मेरे तालचेर का नाम आ जाएगा ...**(व्यवधान)**... बाद में ...**(व्यवधान)**... तालचेर को आरसीएफ को दे रहे हैं, जब उन्होंने ऐसी दूसरी सूची पढ़ी, उसमें इसका नाम आया, पहले जो सूची पढ़ी, उसमें तालचेर का नाम नहीं था। सर, नवम्बर 2006 को माननीय राम विलास पासवान जी को मैंने एक निवेदन पत्र दिया था कि तालचेर के बारे में आप क्या कर रहे हैं। अभी तालचेर के बारे में उनका बयान आया है कि वे तालचेर को revive करने जा रहे हैं। सर, तालचेर में एफसीआई का एक प्लांट है। नेहरू जी के जमाने से, इन्दिरा जी के जमाने से वह प्लांट था। बाद में धीरे-धीरे वह प्लांट बर्बाद हुआ। जैसा कि अमीन साहब ने कहा कि कम्पनियाँ, फैक्टरियाँ बीमार हो रही हैं, बीमारी तो 70 के दशक से चालू हुई है। यह कोई राजनीति की बात नहीं है कि अटल जी के जमाने में बन्द कर दिया गया था।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए न।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा सवाल यह है कि तालचेर के बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं? अभी पिछले दिनों मार्च या अप्रैल में वहाँ ऐसी भयंकर आगजनी हुई ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए, ताकि वे जवाब दें।

श्री रुद्रनारायण पाणिः क्या मंत्री जी को पता है कि अभी मार्च या अप्रैल में वहाँ पर भयंकर आगजनी हुई है और वहाँ सब सूना-सूना लगता है। पास में भले ही एक हेवी वाटर की फैक्टरी भी है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणिः सर, सवाल के माध्यम से मेरा निवेदन भी है कि उड़ीसा एक गरीब राज्य है और वहाँ पर सबसे ज्यादा बीपीएल वाले लोग रहते हैं, वहाँ 46.4 परसेंट बीपीएल है। मंत्री जी के बिहार से भी वह गरीबी में नीचे है। उस राज्य को माननीय मंत्री जी कुछ दें और तालचेर का फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का कारखाना तुरंत कैसे चालू होगा, उसके लिए कुछ कदम उठाएँ।

श्री राम विलास पासवानः सर, पहली बात तो यह है कि उड़ीसा एक गरीब राज्य नहीं है, वहाँ बहुत माइन्स हैं, लोग गरीब जरूर हैं। दूसरी बात यह है कि हमने तो कोशिश की है कि जिसको आपने श्मशान घाट पर पहुँचा दिया था, जिस रोगी को आपने मृत घोषित किया था, उसको हम जिन्दा करने की कोशिश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Let him answer. Hon. Member, please sit down.

श्री राम विलास पासवानः हमारे मंत्रिमंडल से हटने के बाद आपने उसे बन्द किया है। यदि वह sick भी रहता, तो हम उसमें जल्दबाजी कर सकते थे। अब जो कारखाना already बन्द हो चुका है, उसको चालू करने में समय लगता है और यह कम बात नहीं है। आपको यूपीए गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने आठ बंद कारखानों को चालू करते हुए, प्रत्येक जगह पर एक-एक मिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है और जैसा कि मैंने कहा ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालियाः इन्होंने जो उड़ीसा की बात पूछी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवानः एक मिनट ...**(व्यवधान)**... फिर से मैं श्री अहलुवालिया जी और पाणि जी की जानकारी के लिए यह पढ़ देता हूं कि बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, एचएफसी के और गोरखपुर, तल्चर, रामगुडम, सिंदरी एवं कोरबा, एफसीआई के, ये आठ कारखाने हैं, जिन्हें सरकार ने खोलने का निर्णय ले लिया है। आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि जो तल्चर का कारखाना है, आरसीएफ पब्लिक अंडरटेकिंग है और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है, उन्होंने उसे चालू करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है, हम लोग उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ हम पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ गैस की जो एवेलेबिलिटी है, जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ज्यों ही वह हमें मिल जाएगी, वह चालू हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Before I give the floor to the next Member for asking supplementary question, I would like to make one observation. The Question Hour is for asking questions and for obtaining replies from the Government. It is not an occasion for making statements. I would urge all concerned, in the interest of right of other Members who have also to ask questions, simply to ask focussed questions and get focussed answers from the Government. Shri Amar Singh.

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा संचालित ऐसी फर्टिलाइज़र कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं, जो बंद पड़ी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इन फर्टिलाइज़र कंपनियों के बंद होने के कारण अब तक कितने कर्मचारी बेरोज़गार हुए हैं? क्या सरकार इन कंपनियों के पुनरुद्धार की कोई योजना बनाने वाली है?

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने बंद कंपनियों के बारे में बता दिया है, लेकिन जो विशेष जानकारी है, वह मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। चूंकि यह सवाल एमएफएल के ऊपर था, लेकिन आपने जो विशेष जानकारी मांगी है, उसमें से हर प्रश्न का उत्तर मैं जल्द से जल्द माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it is a straight and focussed question. Is it not true that the cost of production of urea in MFL is not the highest in the country but highest in the world? It is good that the Government is trying to restart it, maybe even by 2010-2011. But, till then, how are you going to look after workers who work there? Will the Minister please assure the House that all payments to the workers will be continuously made till 2010-2011? Otherwise, at that time, either the unit will not have workers or the unit will not survive. On one day, you cannot pay all the funds. Can we have this assurance from the Government? Can the House get an assurance from the Government that when this project restarts, the Government will have enough resources to restart the unit? Normally, it has been found that the Government funds only up to 10, 20 or 50 per cent and the result is that the unit again goes in red as it had gone earlier. I urge the Minister to please assure the House in this regard.

श्री राम विलास पासवान: सर, मैं फिर से पूरी जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी गैस बेस्ड प्लांट हैं या होंगे, वे घाटे में नहीं जाएंगे। जहां तक नेफ्था बेस्ड प्लांट्स का प्रश्न है, उसमें आप चाहे कितना भी रिवाइव कीजिए, हालांकि पहले ही उसे तीन बार रिवाइव किया जा चुका है और चौथी बार हम लोग इसे आगे ले करके जा रहे हैं। अब उस पर कैबिनेट क्या करेगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जहां तक रिवाइवल का सवाल है, यह बात सही है कि अगर एक बार यह गैस बेस्ड हो जाता है, हम जब इसे रिवाइव करेंगे, उसमें हम इस बात को जरूर देखेंगे कि जब यह रिवाइव होता है, तो सरकार को 2009-10 तक, जब तक गैस की एवेलेबिलिटी नहीं हो जाती है, तब तक नेफ्था का कॉस्ट इन्हें बीयर करना पड़ेगा।

जो बात आप कह रहे हैं, एमएफएल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वह सबसे हाई है। उस परिस्थिति में सरकार क्या निर्णय लेगी, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ इतनी बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जब यह गैस बेस्ड हो जाएगा, तब इसमें घाटे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

*183. [The questioner (Shri Raj Nath Singh) was absent. For answer *vide* page.....21....infra.]

श्री शरद यादव: सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं। हालांकि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ....**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: The questioner is not here. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं ...**(व्यवधान)** । इस पर साफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिए ...**(व्यवधान)** पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन पूरी तरह चौपट हो गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आज का जो सिस्टम है, मैं उससे चल रहा हूँ ...**(व्यवधान)** If the questioner is not here...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: सर, माननीय मंत्री जी बैठे हैं ...**(व्यवधान)**... वे तैयार हो जाएँ ....**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You have the option of giving notice for Half-an-Hour discussion. Next Question please. Q.No. 184.

New rail lines in Himachal Pradesh

*184. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to construct new rail lines in various States of the country during the year 2007-08;

(b) if so, the sectors where Government propose to construct new rails lines in Himachal Pradesh; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. VELU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. 7 new line proposals have been included in Budget 2007-08.

(b) The new proposals included in the Budget include new line from Chandigarh to Baddi which partly falls in Himachal Pradesh.

(c) Does not arise.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो 7 लाइनें नए प्रोपोज़ल में आई हैं, 2007-2008 के बजट में, वे 7 लाइनें कौन-सी हैं? मैं इनको धन्यवाद करती हूँ कि चंडीगढ़-बड्डी लाइन इस बजट में आई है। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या उसका सर्वे हो गया है? उसके लिए कितने बजट का प्रावधान रखा गया है तथा उसे कब तक शुरू करेंगे?

SHRI R. VELU: Sir, the hon. Member wants to know about the other six projects which have been included in the Budget 2007-08. These projects are Bihta-Aurangabad, Sultanganj-Katuria, Bariarpur-Mananpur, Chandigarh-Baddi, Deoband-Roorkee, Rayadurg-Tumkur, Chota Udeput-Dhar. These are the seven projects, out of which one relates partly to Himachal Pradesh and partly to Punjab.